मुख्य समाचार :–

- राज्य विधानसभा में पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया।
- अनुपूरक बजट में लगभग तीन हजार सात सौ छप्पन करोड़ राजस्व पक्ष में और लगभग एक हजार दो सौ छप्पन करोड़ रुपए का पूंजीगत पक्ष में प्रावधान।
- सदन के दूसरे दिन विपक्ष ने उत्तराखंड विधानसभा में विभिन्न सत्रों की कम समयावधि का मामला उठाया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा –– गैरसैंण का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता।
- मुख्यमंत्री ने टिहरी जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का निरीक्षण किया।

विधानसभा

राज्य विधानसभा के दूसरे दिन आज सदन के पटल पर पांच हजार तेरह करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इस अनुपूरक बजट में लगभग तीन हजार सात सौ छप्पन करोड़ राजस्व पक्ष में और लगभग एक हजार दो सौ छप्पन करोड़ रुपए पूंजीगत पक्ष में है।

केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत एक हजार पांच सौ इक्कतीस करोड़ रुपए और बाह्य सहायतित योजनाओं के तहत दो सौ तिहत्तर करोड़ रुपए का प्रावधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है। बजट में आपदा प्रबंधन विभाग के तहत एस०डी०आर०एफ, समग्र शिक्षा, सूचना विभाग, शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट में वाइब्रेंट विलेज योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

विपक्ष मुद्दे

सदन के दौरान विपक्ष ने उत्तराखंड विधानसभा में विभिन्न सत्रों की कम समय अवधि का मामला उठाया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि विधानसभा सत्र के कम चलने से जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। जनहित से जुड़े कई सवाल और मुद्दे बिना उत्तर दिए रह जाते हैं।

विपक्ष ने नियम 299 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया और सरकार से इस पर जवाब मांगा। हालांकि सरकार की तरफ से आये जवाब पर संतोष जताते हुए पीठ ने नोटिस को खारिज कर दिया। विपक्ष ने पीठ के निर्णय से नाराजगी जताते हुए हंगामा किया।

कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने शून्य काल में सदन की कम समय अवधि का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि संसद समेत देश भर की विधानसभाओं में तीन सत्र के आयोजन का प्रावधान है। इस दौरान कम से कम 60 दिन सदन के संचालन होता है।

विपक्ष की ओर से उठाये गये मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सदन के कामकाज को बाधित किया जाता है। कम समय अवधि पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि सदन की कार्यवाही का समय बिजनेस के आधार पर तय होता है। बिजनेस नहीं है तो सदन में बैठे रहने से कोई लाभ नहीं है।

गैरसैंण विकास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि गैरसैंण का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सालभर विभिन्न प्रशिक्षण, वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जायेंगे। इन कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी सचिव स्तर के अधिकारियों को दी जाएगी। वर्षभर संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिलेगी। श्री धामी ने कहा कि गैरसैंण को योग, ध्यान, अध्यात्म के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री से आज भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में चमोली जिले के विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ पत्रकारों के शिष्टमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्री धामी ने पत्रकारों की माँग पर भराड़ीसैंण में पत्रकारों के लिये विश्राम गृह बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने महानिदेशक सूचना को निर्देशित किया कि इस संबंध में तत्काल कार्ययोजना तैयार की जाए।

रोक हटी

उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की ओर से वर्ष 2023 में आयोजित कृषि और उद्यान विभाग के समूह–ग के रिक्त 637 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणामों पर लगी रोक हटा दी गई है। नैनीताल उच्च न्यायालय की ओर से परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति मिलने के बाद अब सहायक कृषि अधिकारी वर्ग तीन के 354 पद, उद्यान पर्यवेक्षक 245 और सहायक उद्यान अधिकारी 38 नए अधिकारी–कर्मचारी कृषि एवं उद्यान विभाग को मिलेंगे।

लक्ष्य

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की पहल पर प्रदेश में अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य हासिल करने को प्रयास किए जा रहे हैं। जिन जिलों में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई है वहां विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में में प्राधिकरण के अधिकारी बागेश्वर जिले पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जिले में सभी रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित कर सुझाव व रणनीति पर विचार किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक प्रशासन डॉक्टर वीएस टोलिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में बागेश्वर में आयुष्मान योजना की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही बाल विकास, पंचायती राज, पूर्ति विभाग और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य हासिल करने को लेकर मंत्रणा की गई।

एमबीबीएस एडमिशन

राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश का इंतजार खत्म हो गया है। नीट–यूजी स्टेट काउंसलिंग का पहला चरण शुरू हो गया है। इस चरण में आवंटित सीट पर दाखिले पांच सितंबर तक होंगे। प्रदेश में चार सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें कुल 525 सीटें हैं। पहले चरण में पंजीकरण, आवेदन, चयन भरने और फीस जमा कराने के लिए 26 अगस्त अंतिम तिथि है। डाटा प्रॉसेसिंग 27 और 28 अगस्त को होगा। 29 अगस्त को पहले चरण का सीट आवंटन हो जाएगा।

हवाई सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी गढ़वाल जिले की घनसाली तहसील के घुत्तु, पंज्या और देवलिंग क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का हवाई और स्थलीय सर्वेक्षण किया।

इससे पहले, चमोली में पत्रकारों के साथ बातचीत में श्री धामी ने कहा कि अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। मवेशियों, सड़क मार्ग, सरकारी और निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को हर तरह की सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला प्रशासन से उन सभी अन्य गांवों का आकलन करने को कहा गया है जहां ऐसी आपदा की संभावना है। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य तुरंत किए जाएंगे और जल्द से जल्द नुकसान की भरपाई की जाएगी।

इधर, राजधानी देहरादून की सदर तहसील के सौड़ा सरोली में कल रात अतिवृष्टि के कारण मलबा घुस गया। घरों और रास्तों से मलबे को हटाने की कार्यवाही जारी है।

वृद्धि

उत्तराखंड को एस०डी०आर०एफ और एन०डी०आर०एफ की दरों में वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत और जन सामान्य की परेशानियों को दूर करने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के पुनर्निर्धारण कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। सतपाल महाराज ने कहा कि पूर्व में एस०डी०आर०एफ० की मदों में रिकवरी और पुनर्निमाण के लिये मानक तय नहीं थे और दरें भी काफी कम थी। इस कारण आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत कार्य में व्यवहारिक कठिनाइयों सामना करना पड़ता था। लेकिन उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनराशि बढ़ाये जाने की प्रभावी पैरवी की थी। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने रिकवरी और पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत नवीन दिशानिर्देश निर्गत कर विभिन्न कार्यों के लिए लागू मानकों में वृद्धि कर दी है।

पत्रकार वार्ता

राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पांच लोक सूचना और तीन प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आर.टी.आई. दिवस पर बेहतर निष्पादन करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना अधिकार भवन रिंग रोड सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्य प्रभारी सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने कहा कि आमजन में सूचना का अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोग विधि कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। सूचना आयुक्त योगश भट्ट ने बताया कि सूचना अधिकारी से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है।

जाम राहत

अगले वर्ष की चारधाम यात्रा और अन्य त्योहारी सीजन के दौरान उत्तरकाशी में जाम से काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। वाहन चालकों को अपने वाहन सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में खड़े नहीं करने पड़ेंगे। उत्तरकाशी मुख्य बाजार के जियोग्रिडवाल के पास दो मंजिला बस अड्डा और पार्किंग का निर्माण इस वर्ष अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। जियोग्रिडवाल के पास तैयार हो रही पार्किंग में एक ही समय में 22 बसें, 40 टैक्सियां और 120 से अधिक दोपहिया वाहन पार्क किये जा सकते हैं। अभी इस पार्किंग का 95 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है। पेयजल निगम के अनुसार मानसून सीजन समाप्त होते ही शेष पांच प्रतिशत कार्य एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा।

अधियाचन

उत्तराखंड लोअर पीसीएस भर्ती का अधियाचन तैयार हो गया है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेज दिया। इसमें 117 पदों पर भर्ती की संस्तुति की गई है। अधियाचन में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इसके तहत कुल सात पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें नायब तहसीलदार के तीन, उप कारापाल का एक, पूर्ति निरीक्षक के तीन पद शामिल हैं। प्रदेश में लोअर पीसीएस की आखिरी भर्ती 2021 में निकली थी।